वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18

समावेशी प्रगति के लिए समर्पित

POWERING INCLUSIVE GROWTH

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री एन. दामोदरन (कार्यपालक निदेशक), श्री देबब्रत सरकार, श्री डी. हरीश, श्रीमती वेनी थापर, श्री दीनबंधु मोहापात्रा (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ), श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्रीमती आर सेबॅस्टियन, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री ए. के. दास (कार्यपालक निदेशक), श्री सी. जी. चैतन्य (कार्यपालक निदेशक)

Shri N Damodharan (Executive Director), Shri Debabrata Sarkar, Shri D Harish, Ms. Veni Thapar, Shri Dinabandhu Mohapatra (Managing Director & CEO), Shri G Padmanabhan (Chairman), Ms. R Sebastian, Shri Girish Chandra Murmu, Shri A K Das (Executive Director), Shri C G Chaitanya (Executive Director)

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : headoffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	10 जुलाई, 2018 सुबह 10.00 बजे से 12 जुलाई 2018 शाम 5.00 बजे तक	E- Voting dates	10th July 2018 10 a.m. to 12th July 2018 Till 5.00 p.m.
लेखाबंदी तिथि	9 जुलाई 2018 से 12 जुलाई 2018	Book Closure	9th July 2018 to 12th July 2018
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	शुक्रवार, 13 जुलाई 2018 सुबह 10.30 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Friday 13th July 2018 at 10.30 a.m.
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम स्टार हाऊस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2 सांविधिक लेखा परीक्षक
2 महाप्रबंधक
3 अध्यक्ष का संबोधन
6 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

2 Statutory Auditors
2 General Managers
3 Chairman's Statement
6 Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

10 निदेशक रिपोर्ट
14 प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण
41 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
42 कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट
60 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
60 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
169 बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन
229 आम बैठक की सूचना

12 Directors' Report
28 Management Discussion & Analysis
41 Corporate Social Responsibility Report
42 Corporate Governance Report
60 CEO/CFO Certificate
60 Declaration by CEO
200 Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
229 Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

62 तुलनपत्र
63 लाभ एवं हानि खाता
64 नकदी प्रवाह विवरण
72 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
84 खातो के भाग स्वरुप टिप्पणियां
123 स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट
127 समेकित वित्तीय विवरण

62 Balance Sheet
63 Profit & Loss Account
64 Cash Flow Statement
72 Significant Accounting Policies
84 Notes Forming Part of Accounts
123 Independent Auditor's Report
127 Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स जी.डी.आपटे एण्ड कंपनी	M/s. G D Apte & Company
मेसर्स एनबीएस एण्ड कंपनी	M/s. NBS. & Company
मेसर्स बंसी जैन एण्ड एसोसिएट्स	M/s. Banshi Jain & Associates.

महाप्रबंधक General Managers

देवेन्द्र शर्मा (सी वी ओ)	DEVENDRA SHARMA (CVO)
शंकरदास गुप्ता	SHANKARDAS GUPTA
एस.आर. मीणा	SHEOJI RAM MEENA
अनन्त उपाध्ये	ANANT UPADHYAY
ब्रजेश कुमार मोहन्ती	BRAJESH KUMAR MOHANTY
अज्ञेय कुमार आज़ाद	AGYEY KUMAR AZAD
दिनेशकुमार गर्ग	DINESHKUMAR GARG
राजकुमार सिंह चौहान	RAJKUMAR SINGH CHOUHAN
मृत्युंजय कुमार गुप्ता	MRITYUNJAY KUMAR GUPTA
श्याम सुंदर बनिक	SHYAM SUNDAR BANIK
रमेश चंद ठाकुर	RAMESH CHAND THAKUR
प्रसाद अंबादास जोशी	PRASAD AMBADAS JOSHI
राज कुमार मित्रा	RAJ KUMAR MITRA
सुदीप्त कुमार मुखर्जी	SUDIPTA KUMAR MUKHERJEE
रवि प्रकाश गुप्ता	RAVI PRAKASH GUPTA
अरविंद वर्मा	ARVIND VERMA
विश्वनाथ गुंटा	VISWANATH GUNTA
स्वरूप दासगुप्ता	SWARUP DASGUPTA
आदर्श कुमार अरोड़ा	ADARSH KUMAR ARORA
एस रवि कुमार जोयसुला	S. RAVI KUMAR JOSYULA
सलिल कुमार स्वाईं	SALIL KUMAR SWAIN
जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव	JITENDRA KUMAR SRIVASTAVA
अश्विनी कुमार पुन	ASHWANI KUMAR PUNN
राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव	RAJENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
देवेंद्र पी. शर्मा	DEVENDER P. SHARMA
के राजारामन	K RAJARAMAN
राजेंद्र नारायण हरिचन्दन	RAJENDRA N. HARICHANDAN
अरुण कुमार मण्डल	ARUN KUMAR MANDAL
सुनील कुमार रेलन	SUNIL KUMAR RELAN
गौर हरि सारंगी	GOURA HARI SARANGI
मिलिंद माधव वैद्य	MILIND MADHAV VAIDYA
पर्शुराम पंडा	PARSHURAM PANDA
अजय कुमार साहू	AJAY KUMAR SAHOO
चन्द्र शेखर सहाय	CHANDRA SHEKHAR SAHAY
शंकर प्रसाद	SHANKER PRASAD
अरुण कुमार जैन	ARUN KUMAR JAIN
के. व्ही. राघवेंद्र	K.V. RAGHAVENDRA
एम नसीम अहमद अंसारी	M NASEEM AHMED ANSARI
मनोज दास	MONOJ DAS
सुरेश कुमार वर्मा	SURESH KUMAR VERMA
लाल बृज	LAL BRIJ

अध्यक्ष का संबोधन
Chairman's Statement

प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. विगत वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 आर्थिक एवं बैंकिंग क्षेत्र का एक विविधतापूर्ण एवं नित्य बदलनेवाला परिदृश्य प्रस्तुत करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2011 से 3.8% पर सबसे तीव्रतम वृद्धि नज़र आई; जबकि घरेलू आर्थिक वृद्धि काफी मंद रही। वर्ष 2017 के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2.3% वृद्धि हुई और उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्ताओं में 4.8% वृद्धि हुई। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश-व्यय में पुनरुत्थान, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निजी खपत में वृद्धि और वैश्विक व्यापार में पुन: आई तेज़ी ने वृद्धि की गति को बनाए रखा।

2. तथापि, पुन: बढ़ने वाली इस वृद्धि के साथ-साथ उपयोगी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। सकारात्मक आर्थिक वृद्धि और बेरोज़गारी के दर में गिरावट ने यूएसए को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज दर नीति तीन बार बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। यह आशा की जाती है कि ब्याज दरों के सामान्यकरण की यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी जारी रहेगी, जिससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्याज दरों में वृद्धि और पूँजी प्रवाह पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

3. हालांकि आर्थिक वृद्धि में आई उछाल हम सबके लिए हर्ष की बात है, यह समय है जब आर्थिक इकाइयों को अत्यधिक जोखिम लेने और जोखिम के गलत मूल्य निर्धारण से बचना चाहिए, जिससे भविष्य में वित्तीय असंतुलन पैदा हो सकता है।

4. वैश्विक वृद्धि के इस दौर में, तथापि भारत को वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6.7% की जीडीपी वृद्धि-दर का सामना करना पड़ा। इसका प्रमुख कारण, विमुद्रीकरण एवं जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आए अवरोध थे। इसके अलावा मुद्रा को कठोर बनाने के उपायों के कारण भी उपभोग एवं निवेश-मांग में कमी आई।

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. The year gone-by i.e. FY 2017-18 presents a varied and kaleidoscopic view of the economic and banking sector. The global economy witnessed fastest growth rate at 3.8% since 2011 while domestic economic growth remained somewhat muted. The advanced economies grew by 2.3% and emerging and developing economies by 4.8% during 2017. The resurgence in investment spending in advanced economies, upward movement in private consumption in emerging and developing economies coupled with rebound in global trade has kept up the growth momentum.

2. The resurgent growth, however, has been accompanied with the rise in commodity prices and building up of inflationary pressure. The uptick in economic growth and drop in unemployment rate has prompted USA to raise its policy interest rate thrice during the year FY 2017-18. This process of normalization of interest rate is also expected to continue during FY 2018-19, which have significant implications for emerging economies in terms of hardening of interest rate and possible adverse impact on capital flows.

3. Although buoyancy in economic growth is a matter of satisfaction for all of us , it is the time, when the economic units have to guard them against excessive risk taking and mispricing of risk, which may sow the seeds of future financial imbalances.

4. Amidst the world growth story, however, India stood 'de-coupled', with a GDP growth rate of 6.7% during FY 2017-18 against growth rate of 7.1% during FY 2016-17, primarily due to temporary disruption of economic activities because of demonetization and implementation of GST, apart from the fact that monetary tightening measures also had the sobering effect on consumption and investment demand.

5. वर्ष के दौरान भारत के लिए प्रसन्नता के विषय रहे हैं। "व्यवसाय में सुगमता सूचकांक में हमारे देश ने 190 देशों में 100 वाँ स्थान प्राप्त किया तथा इस रैंकिंग में 30 स्थानों का सुधार आया। हम तब भी प्रसन्न हुए जब मूडी इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत सरकार के स्थानीय तथा विदेशी करेंसी जारीकर्ता रेटिंग को बी.ए.ए.2 से बी.ए.ए.3 के स्तर पर अपग्रेड किया तथा ऑउटलुक पर रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक किया जो 13 वर्षों के बाद हुआ, परन्तु हम यह भी महसूस करते हैं कि यह देश की क्रेडिट स्थिति को देर से पहचानना है।

6. बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में आस्ति की गुणवत्ता तथा पूँजी आवश्यकताओं पर दबाव था एवं बैंक की आय बॉन्डपर यील्ड के बढ़ने के कारण प्रभावित हुई परन्तु वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि कुछ सम्मानजनक रही। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनर्जक ऋण के प्रावधान के कारण भारी प्रभाव पड़ा तथा लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा निवल हानि दर्ज की गयी।

7. पिछले कुछ वर्षों से निश्चित रूप से एन.पी.ए. की पहचान तथा समाधान भारतीय बैंकिंग के केन्द्र में रहा है। अब हम विशेष रूप से कॉरपोरेट ऋणों के संदर्भ में बढ़ते एन.पी.ए. के समाधान के लिए इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्टसी कोड (आई.बी.सी.) फ्रेमवर्क पर आशा एवं उम्मीद से देख रहे हैं। यद्यपि विभिन्न एन.सी.एल.टी. बेंचों के द्वारा 500 से अधिक इन्सॉल्वेंसी मामले स्वीकार किये गये हैं, परन्तु ज्यादातर मामलों में समाधान होना अभी बाकी है। यहाँ यह उल्लिखित करना प्रासंगिक होगा कि आई.बी.सी. के अंतर्गत समाधान न केवल बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु पूरी अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह तथा आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

8. पी.एस.यू. बैंकों के बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए तथा पूँजी पर्याप्तता के विनियामकीय नियमों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा घोषित रु.2.11 लाख का री-कैपीटलाइजेशन पैकेज भरोसा दिलाने वाला तथा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहा है। परन्तु पूँजी प्रदान करने के साथ-साथ बैंकों को विभिन्न सुधार उपाय लागू करने के लिए कहा गया है जिसे इन्हान्स्ड एक्सेस एण्ड सर्विस एक्सेलेन्स (ई.ए.एस.ई.) नाम दिया गया है जिसमें बेहतर ग्राहक सेवाएं, त्वरित गति से डिजिटलीकरण, ऋण मूल्यांकन को मजबूत करना, ऋण निगरानी प्रणाली, ऋण को प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह शामिल है।

9. भविष्य में, बैंकिंग क्षेत्र को आकार देने में विभिन्न कारक भूमिका अदा करेगें। डिजिटाइजेशन इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके माध्यम से बैंक न केवल अपनी पहुंच और उपयुक्तता/उत्कृष्टता बढ़ाएगें बल्कि, यह परिष्कृत परिचालन दक्षता और ग्राहक आधार में विस्तार के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बढत भी सिद्ध होगा। तथापि, डिजिटलीकरण विशुद्ध अनुग्रह मात्र नहीं है, डिजिटलीकरण की सफलता के लिए साइबर सुरक्षा उपाय अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

10. इसी प्रकार, बैंकिंग में विशेषत: रिटेल/वाणिज्यिक उधार और भुगतान के क्षेत्र में फिनटेक (fintech) की पैठ तेजी से बढ़ रही है और फिनटेक कंपनियों और बैंकों के मध्य यह साझेदारी दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। फिनटेक के माध्यम से बैंक नवोन्मेषी और विशिष्ट उत्पाद प्रदान कर सकते हैं, बड़े कारोबारी लेन-देन सृजित कर सकते हैं और सेवा प्रदान करने की समय सीमा (Turn–around-time) (TAT) घटा सकते हैं।

5. There have been occasions for cheers for India. The country improved its ranking by 30 notches to secure 100th place among 190 countries in "Ease of doing Business". All of us also felt delighted, when Moody's Investors Services upgraded the Government of India's local and foreign currency issuer ratings to Baa2 from Baa3 and changed the outlook on the rating to stable from positive, which happened after a long 13 years, although we feel it was a delayed recognition of our county's credit standing.

6. In the Banking and Financial sphere, there was a pressure on asset quality and capital requirement and Banks earnings were affected due to rising yield, although credit growth during the year remained somewhat decent. The bad debt provisioning has taken a heavy toll in terms of net loss posted by almost all the Public sector banks during the year FY 2017-18.

7. The recognition and resolution of NPAs, of course, have remained at the centre stage for Indian Banks for quite a couple of years. All of us are now pinning hope on the Insolvency Bankruptcy Code (IBC) framework for resolution of mounting NPAs, especially of corporate ones. Although more than 500 corporate insolvency cases have been admitted by various NCLT benches, resolution in majority cases is yet to happen. It is quite pertinent to mention that, resolution under IBC is not only crucial for banks, but also critical for the economy as a whole for augmenting credit flow and supporting economic growth.

8. The re-capitalization package of Rs.2.11 lakh crore announced by the Government to strengthen the balance sheet of the PSU banks and enable them to fulfill the regulatory norms for capital adequacy has been quite re-assuring and confidence boosting. However, along with capital infusion, the banks have been advised to implement various reform measures under six broad agenda called Enhanced Access and Service Excellence (EASE) including better customer services, fast paced digitization, strengthening credit appraisal, credit monitoring system, improving credit delivery and credit flow to MSME sector.

9. Going forward, banking space will be shaped by a host of factors. Digitisation is one of the prominent factors, through which banks would not only extend their outreach and convenience/excellence in services, but also it will prove to be a competitive advantage through enhanced operational efficiency and expansion of customer base. However, digitalization is not entirely an unmixed blessing. Crucial to the success of digitization is strengthening of cyber security measures.

10. Similarly, the penetration of Fintech in Banking especially retail/commercial lending and payment space is fast progressing and partnership between the Fintech companies and banks can be a win win situation for both. Through Fintech, banks can provide innovative and niche products, generate large business transactions, can be able to reduce delivery in turn-around-time (TAT).

11. अन्त में, नवीनतम आर्थिक पूर्वानुमान एक अच्छी खबर है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आशा की एक किरण उजागर करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2018 और 2019 में मजबूत वैश्विक वृद्धि 2018 और 2019 में का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के साथ-साथ आरबीआई दोनों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 7.4% की उच्चतर घरेलू वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। यह उत्साहवर्धक आर्थिक वृद्धि न केवल ऋण की मांग को और अधिक बढ़ाएगी बल्कि यह ऋण चुकौती के लिए भी सहायक होगी और इस प्रकार ऋण बकाया में कमी होगी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईबीसी के अंतर्गत बड़े दाबावग्रस्त कॉरपोरेट खातों की समाधान प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है और उनके समाधान से वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। सरकार से प्राप्त पूंजी सहयोग और सुधार उपायों के क्रियान्वयन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आने वाले वर्षो में और अधिक शक्तिशाली, स्वस्थ और प्रगति उन्मुख बैंक बनाने की ओर अग्रसर हैं।

(जी. पद्मनाभन)

11. Lastly, the latest economic forecast augurs well and brings in optimism for FY 2018-19. The IMF, in its latest World Economic Review, has projected the strengthening of global growth through 2018 and 2019. Both the IMF as well as RBI have also projected higher domestic growth rate of around 7.4% during FY 2018-19. The encouraging economic growth will not only further activate credit demand, but also it will be conducive for credit repayment and thus reduce delinquency. The resolution of large stressed corporate accounts which are being processed under IBC is likely to be expedited during FY 2018-19 and their resolution will create space for growth. With the capital support from the Government and implementation of reform measures, public sector banks are now poised to transform themselves into stronger, healthier yet growth oriented banks in coming years.

(G. Padmanabhan)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य
Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. सबसे पहले मैं आप सब का आपके बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है, कि मुझे दूसरी बार आपको संबोधित करने का अवसर मिला है और मैं आप सब का आभारी हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण समय में मुझे आप सब का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

2. वर्ष 2017-18 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उत्साहजनक वर्ष रहा है, जिसमें विकसित एवं उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रगति हुई है। वैश्विक व्यापार में निवेश वसूली एवं पुनरूत्थान से इस वृद्धि को व्यापक आधार मिला है। इस वैश्विक वृद्धि को दिसंबर 2017 में यू.एस. द्वारा शुरू किए गए वित्तीय उत्प्रेरक उपायों एवं कर सुधार के कारण भी प्रोत्साहन मिला है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में सतत उत्साह की स्थिति ने फेडरल रिजर्व और कई अन्य केन्द्रीय बैंकों को ब्याज दर बढ़ाने एवं ईज़ी मनी उपायों को धीरे धीरे हटाने को प्रोत्साहित किया। घरेलू स्तर पर अनेक नीतिगत सुधार शुरू किए गए। जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) शुरू किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत बड़े खातों का समाधान शुरू किया गया। भारत विविध सुधारात्मक उपायों के कारण विश्व बैंक की आसानी से कारोबार करने वाली श्रेणी में 30 स्थानों का सुधार कर 100वें स्थान पर पहुँचा। तथापि आर्थिक घरेलू वृद्धि, गत वर्ष 7.1% की तुलना में 6.7% रही जिसका कारण था, कृषि वृद्धि (6.3% की तुलना में 3.4%) एवं विनिर्माण क्षेत्र (गत वर्ष के 7.9% की तुलना में 5.7%) दोनों में कम वृद्धि। घरेलू वृद्धि को, विमुद्रीकरण की शीघ्रावधि प्रभाव और जीएसटी लागू करने की वजह से आर्थिक गतिविधियों में अस्थायी अवरोधों ने काफी हद तक प्रभावित किया।

3. घरेलू स्तर पर वृद्धि एक सीमा तक विमुद्रीकरण के कारण पिछड़ी और GST के लागू करने के कारण अस्थायी रूप से आर्थिक तौर पर प्रभावित हुई । बैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2016-17 के ऋणवृद्धि के दौरान 8.2% की ऋण वृद्धि की तुलना

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 22nd Annual General Meeting of your Bank. I am privileged enough to address you for the second time and am thankful to you all for placing your unstinted support in this challenging times. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2018.

2. The year 2017-18, has been a very fulfilling year for the global economy with upswing in world output continuing both in developed and emerging economies. The world output growth has strengthened in 2017 to 3.8%. The growth has been broad based supported by investment recovery and resurgence in global trade. The impetus for global growth also came from the tax reforms and fiscal stimulus measures introduced by US in December, 2017. On the other hand, continued buoyancy in economy has prompted Federal Reserve and several other Central Banks to raise the interest rates and initiate gradual withdrawal of the monetary easing measures. Domestically, a slew of policy reforms were initiated. The Goods and Service Tax (GST) was introduced in July, 2017. Resolutions of large accounts under Insolvency and Bankruptcy Code were initiated by the RBI. Because of various reforms measures, India improved its position by 30 places by moving onto 100th place on the World Bank's ranking of Ease of Doing Business. However, domestic economic growth remained muted at 6.7% against 7.1% witnessed last year because of lower growth in both agriculture (3.4% against 6.3%) and manufacturing sector (5.7% against 7.9% of last year). The domestic growth, to a major extent, was impacted by the lingering effect of demonetisation and temporary dislocation of economic activities due to introduction of GST.

3. The Banking System witnessed healthy credit growth during FY 2017-18 at 10.3% against 8.2% during FY 2016-17. The

में वर्ष 2017-18 में 10.3% की उत्साहजनक वृद्धि हुई। जमाराशियों में वृद्धि वित्त वर्ष 2016-17 के 15.3% की तुलना में कम होकर 6.7% रहीं।

4. वर्ष के दौरान, सरकार और आरबीआई ने कई नीतिगत घोषणाएं की हैं जिनका बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु रु.2.11 लाख करोड़ के पुन:पूंजीकरण की योजना बनाई, जिससे बैंकों को बहुत राहत मिली, पुन:पूंजीकरण के साथ-साथ, सरकार ने 'इन्हान्स्ड ऐक्सेस एण्ड सर्विस एक्सलेन्स'(EASE) नामक बैंकिंग सुधार (reforms) उपाय शुरू किया है, जो बैंकों को और अधिक ग्राहक-उन्मुख, प्रतिस्पर्धी और आंतरिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा और बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेगा। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव के प्रभाव को कम करने हेतु कुछ उपाय किए हैं जैसे- भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards) को एक वर्ष के लिए स्थगित करना, एमएसएमई को बकाया भुगतानों पर छः महीने की ऋण-स्थगन अवधि की अनुमति प्रदान करना, प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने हेतु एमएसएमई क्षेत्र हेतु निर्धारित सीमाएं हटाना, एमटीएम प्रावधानों को चार तिमाहियों में बांटने (spread) हेतु बैंकों को अनुमति देना आदि। पिछले महीनों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में कई संशोधन किए गये हैं जिनसे एनसीएलटी के तहत मामलों का समाधान करने की प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। आरबीआई अधिसूचना दिनांक 12.02.2018 एक ऐसा महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तन है जिसका, कम-से-कम लघु अवधि में, बैंकों के तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, हालांकि भारत में सुदृढ़ ऋण-संस्कृति विकसित करने की दृष्टि से इससे दीर्घावधि लाभ मिलेगा।

5. वर्ष 2017-18, कई मामलों में भारतीय बैंकों के लिए उथल-पुथलपूर्ण रहा। आरबीआई ने बैंकों को यह अधिदेशित किया कि वे आईबीसी के तहत, बड़े एनपीए खातों का समाधान करें। प्रारम्भ में 12 बड़े चूककर्ता उधारकर्ताओं के लिए यह समाधान करना है जिनका सकल एनपीए में कुल बैंकिंग सिस्टम का 25% हिस्सा है। बाद में 29 बड़े खातों का समाधान किया जाए। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों एवं बॉण्ड्स का प्रतिफल वर्ष के अधिकांश भाग हेतु 8.0% के आसपास रहा, जिसके फलस्वरूप बैंकों की गैर-ब्याज आय तो प्रभावित हुई है, साथ में इस वजह से उच्चतर एमटीएम प्रावधान भी करना पड़ा। पीएनबी द्वारा जारी वचन पत्र (LoU) के मामले में लगभग रु.13,000 करोड़ के धोखाधड़ीपूर्ण संव्यवहारों से पूरे बैंकिंग उद्योग का संतुलन बिगड़ गया।

6. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आपके समक्ष वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पहल और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत करता हूँ।

7. **बैंक का कार्यनिष्पादन**

- संभाव्यताओं का दोहन करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान अनेक नई पहल की। जिनमें **"प्रोजेक्ट कनेक्ट-संपर्क"** के अंतर्गत व्यवसाय विकास तथा आस्ति गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए क्षेत्र प्रबंधकों की तैनाती करना तथा सभी विशिष्ट ग्राहकों के लिए **"स्टार प्राइम"** की अवधारणा शामिल है।
- विकास की संभावना वाले केन्द्रों पर व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए **"स्टार प्वाइंट"** नाम से (731) व्यवसाय प्रतिनिधि आधारित आउटलेट खोले गये हैं। ग्राहकों को उत्कृष्ट डिजिटलीकृत बैंकिंग सेवा देने के लिए 113 शाखाओं को **स्टार डिजी शाखाओं** के रूप में पुन: डिजाइन किया गया है।
- आपके बैंक की आई.टी. क्षमता को मजबूत किया जा रहा है तथा इसके लिए **"स्टार महाशक्ति"** परियोजना को आरंभ किया गया है। यह बैंक के आइटी बेस को अपग्रेड करेगा तथा कोर बैंकिंग समाधान को अगले स्तर पर ले जायेगा।
- **"आमंत्रण"** नामक विशेष कासा अभियान आयोजित किया गया जिसमें "GABHI" खातों (सरकार, संघ/क्लब/सोसाइटियों, कारोबारी ग्राहकों, उच्च निवल आय व्यक्तियों तथा गैर-निवासी भारतीयों एवं संस्थाओं) पर विशेष ध्यान दिया गया।

deposits growth, however, remained subdued with growth rate of 6.7% against 15.3% during FY 2016-17.

4. During the year, several policy pronouncements were made by the Government and the RBI and some of them have far reaching implications for the banking sector. The Government came out with recapitalization of public sector banks to the tune of Rs.2.11 lakh crore, which has come as a great relief for banks. Along with recapitalization, the Government has also introduced Banking Reforms measures called - Enhanced Access and Service Excellence (EASE), which will define future contours of Banking Sector, by making banks more customer oriented, more competitive, yet internally strong. Some of the RBI measures which has lessened the impact of stress on banking sectors are :- deferring Indian Accounting Standards norm by one year, allowing six months moratorium to specified categories of MSMEs on overdue payments, removing limits stipulated for MSME sector for inclusion in priority sector, allowing banks to spread over MTM provisions over four quarters. For last six months, we have seen a host of facilitating amendments to the Insolvency and Bankruptcy Codes, which will ease the process of resolution of cases under NCLT. One of the significant regulatory changes which have significant impact on banks' balance sheet and P&L, at least in short term, is of course RBI's notification of February 12, 2018, although it will have long term benefits for developing a sound credit culture in India.

5. The year 2017-18 has also been a tumultuous year for Indian banks on several counts. The RBI mandated banks for resolution of large NPA accounts under IBC, initially for 12 large defaulting borrowers accounting for 25% of the Gross NPAs of banking system and later 29 large accounts. Secondly, the G-sec and bond yields for most part of the year remained elevated almost touching 8.0%, thus not only impacting the non-interest income of banks, but also entailing upon higher MTM provisions. The entire banking Industry was rocked with around Rs.13,000 crore fraudulent transactions in case of Letter of Undertaking issued by PNB.

6. Against the above backdrop, let me present before you the major initiatives taken by your bank during the year as well as the highlights of the Bank's performance during FY 2017-18.

7. **BANK'S PERFORMANCE**

- Your Bank, during 2017-18, embarked upon several new initiatives for unlocking the potential. Among them were concept of **"Project Connect- Sampark"** with posting of Area Managers at the grass root level to take care of business development and assets quality and concept of **"Star Prime"** for all Prime Clients.
- For tapping the business of potential Growth Centres, Business Correspondent based outlets called **Star Points** (731) have been opened. For offering high end digitalized banking services to customers, 113 branches have been redesigned as **Star Digi Branches**.
- The IT capability of your Bank is being strengthened and for this, project **'Star Mahashakti'** has been launched, which will upgrade the IT base of the Bank to the next level of Core Banking Solution.
- Special CASA campaigns **"Amantran"** were organized with special focus on **"GABHI"** accounts (Government, Associations/ Clubs/ Societies, Business Clients, HNIs / NRIs and Institutions).

- स्वर्ण ऋण खण्ड में बैंक की पहुँच को बढ़ाने के लिए **"स्वर्ण धारा"**नामक नई योजना आरंभ की गयी।
- एनपीए के त्वरित समाधान के लिए **"मिशन समाधान"** नामक योजना आरंभ की गयी है जो गैर-विभेदकारी तथा गैर-पक्षपाती है।
- वर्ष 2017-18 में समेकन एवं पूंजी संरक्षण बैंक की स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रमुख निर्देशक रहे हैं। तुलनात्मक रूप से जहाँ मार्जिन/प्रतिफल अधिक है, उन स्थानों को संसाधन प्रदान करने के विचार से बैंक ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का समेकन किया है। 2017-18 में पूरे साल पूरी तरह से अभियान मोड में रहकर आपके बैंक ने निरन्तर एनपीए की वसूली, रिटेल ऋण की वृद्धि तथा कासा को प्राप्त करने का अनवरत प्रयास किया है। वर्ष के दौरान बैंक की कुछ उपलब्धियों को मैं रेखांकित करूंगा।
- यथा 31 मार्च 2018 आपके बैंक का वैश्विक व्यवसाय रु.8,96,850 करोड़ रहा। बैंक का वैश्विक जमा रु.5,20,854 करोड़ तथा वैश्विक सकल अग्रिम रु.3,75,995 करोड़ रहा।
- आपके बैंक का कासा अनुपात बेहतर होकर मार्च 2017 के 39.84% की तुलना में मार्च 2018 में 41.43% हो गया। बैंक के द्वारा की गयी विभिन्न पहलों के कारण कासा का स्तर मार्च 2017 के रु.1,66,608 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में रु.1,72,787 करोड़ हो गया।
- बैंक अपने अग्रिम पोर्टफोलियो को संतुलित करने के पथ पर है तथा इसके लिए इसने विचारपूर्वक जोखिम का विविधीकरण, पूँजी का संरक्षण तथा ज्यादा प्रतिफल की संभावना को ध्यान में रखा है। फलस्वरूप, आरएएम अग्रिम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) में यथा 31 मार्च, 2017 में रु.1,37,156 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2018 में रु.1,50,924 करोड़ हुये हैं एवं अग्रिमों में इनकी हिस्सेदारी मार्च 2017 में 48.00% से बढ़कर मार्च 2018 में 51.42% हुई है। इनमें से, रिटेल अग्रिम यथा 31 मार्च, 2018 को 19.25% वृद्धि के साथ रु. 47,817 करोड़ पर पहुंच गए।
- आपके बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में विनियामक मानदण्डों को प्राप्त किया है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु.1,21,691 करोड़ रहा, जो कि एएनबीसी का 40.80% है। इस प्रकार कम ब्याज सहित आरआईडीएफ में जबरन निवेश करने से बैंक बच गया। कृषि अग्रिम रु.51,938 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 18.58% था।
- सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2017 (जब आरबीआई ने पीसीए प्रस्तावित किया) के 16.93% की तुलना में बेहतर होकर मार्च 2018 में 16.58% हुआ है। उसी प्रकार, आरबीआई द्वारा एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किए गए एसबीएलसी के समक्ष रु. 9000 करोड़ के ऋणों की जोरदार वसूली के कारण निवल एनपीए अनुपात को दिसंबर में 10.29% से घटकर मार्च, 2018 में 8.26% हुआ है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात में क्रमिक एवं वर्ष-दर-वर्ष दोनों आधार पर सुधार हुआ। इसमें मार्च, 2017 में 61.47% एवं दिसंबर 2017 में 56.96% से मार्च 2018 में 65.85% का सुधार हुआ है।
- जमा लागत एवं निधि लागत दोनों को कम किया गया है। घरेलू जमाओं की लागत जो मार्च, 2017 के 6.04% थी से घटाकर मार्च, 2018 में 5.52% कर दिया गया है एवं उसी अवधि के दौरान निधि लागत को 5.48% से घटाकर 5.09% किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके बैंक का परिचालन लाभ रु.7,139 करोड़ एवं निवल लाभ (-) रु.6,044 करोड़ है। वर्ष के दौरान अन्य सभी बैंकों के मामले में बैंक का लाभ नए विनियामक मानदण्डों के अनुवर्ती अतिरिक्त एनपीए प्रावधानों एवं न्यून कोषागार आय एवं एमटीएम प्रावधानों के कारण भी प्रभावित हुआ है।

- For larger penetration of the Bank into the Gold Loan segment, a special scheme **"Swarna Dhara"** was formulated.
- A non-discriminatory and non-discretionary OTS Scheme called **"Mission Samaadhan"** was formulated for quick resolution of NPAs.
- Consolidation and Capital Conservation has been the guiding force for the Bank for FY 2017-18. Particularly, the Bank went for a consolidation of international business, with a view to allocate resources to the avenues where margin/returns are relatively higher. Your Bank also relentlessly strived for Recovery of NPAs, expansion of Retail Credit and augmentation of CASA in a virtually campaign mode throughout the year 2017-18. I will highlight some of the achievements by the Bank during the year.
- Your Bank's Global Business stood at Rs.8,96,850 crore as on March 31, 2018. The Global Deposits of the Bank stood at Rs.5,20,854 crore and Global Gross Advances at Rs.3,75,995 crore.
- The CASA ratio of your Bank improved from 39.84% in March, 2017 to 41.43% in March, 2018. The CASA level moved up from Rs.1,66,608 crore in March, 2017 to Rs.1,72,787 crore in March, 2018 as a result of various initiatives taken by the Bank.
- The Bank, as a conscious decision for diversification of risks, capital conservation and prospects of higher returns, has been on a path of rebalancing of advances portfolio. As a result, the RAM Advances (Retail, Agriculture and MSME) increased from Rs.1,37,156 crore as on March 31,2017 to Rs.1,50,924 crore as on March 31, 2018 and its share in Advances increased from 48.00% in March 2017 to 51.42% in March 2018. Among these, the Retail Advances posted a 19.25% growth to reach Rs.47,817 crore as on March 31, 2018.
- Your Bank has achieved the regulatory norms with regard to the Priority Sector Advances, which stood at Rs.1,21,691 crore constituting 40.80% of ANBC and thereby avoiding forced investment in RIDF with very low interest. Agriculture advances were Rs.51,938 crore forming 18.58% of ANBC.
- The Gross NPA ratio improved sequentially from 16.93% in December, 2017 (When RBI proposed PCA) to 16.58% in March 2018. Similarly, the net NPA ratio declined from 10.29% in December, 2017 to 8.26% in March, 2018 by aggressively recovering Rs.9,000 crore loan against SBLC which were downgraded as NPA by RBI.
- Provision Coverage Ratio improved, both sequentially as well as on y-o-y basis. From 61.47% in March, 2017 and 56.96% in December 2017, it has improved to 65.85% in March 2018.
- Both the cost of deposits and cost of funds have been brought down. The domestic cost of deposits has been brought down from 6.04% in March, 2017 to 5.52% in March, 2018 and cost of funds has been curtailed from 5.48% to 5.09% during the same period.
- Your Bank's Operating Profit stood at Rs.7,139 crore and Net Profit at (-) Rs. 6,044 crore in FY 2017-18. The Bank's profits, as in case of all other banks during the year, has been impacted by additional NPA provisions consequent to the new regulatory norms and also because of lower treasury income and MTM provisions.